(b) whether it is a fact that Government, Private and Co-operative Sectors pay different pprices of sugarcane to the farmers; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V SWAMINATHAN): (a) to (c) The Government flxeg only the ^atutory minimum cane price payable by each factory linked to a base recovery with a premium for higher recoveries. This will difEer from factory to factory depending on recovery. No factory can pay less than this. The factories may, however, pay higher prices ^s dictated by the forces of supply and demand. In the latter case the prices paid may in some zones be uniform, if the agreed prices are fixed without linkage to recovery. The practice (whe^er among private, cooperative or Government factories) differs from State to State depending on local circumstances and the ability of factories to pay above the statutory minimum.

Opening of Post Offices

256. SHRI M. BASAVARAJU: Will. the Minister of COMMUNICATIONS \ be pleased to state;

(a) the number of Post Offices likely to be opened during 1981-82; and

(b) the mmiber of Post Offices opened during 1980-81 ?

THE DEPUI'Y MINISTER IN THE j MINISTRY OF COMMUNICATIONS ' (SHRI VUAY N. PATIL): (a) Dtiring the year 1981-82, it is proposed to open 1600 rural post offices ih the country. There are no specific targets for opening of post offices in urban areas.

(b) The total number of post offices opened during 1980-81 (as o" 31-2-80) ia 1725.

Poor efficiency of Telecommunication Wing

257. SHRI M. BASAVARAJU: Will the Minister of COMTMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that poor efficiency of the Telecommunication Wing of the Ministry has been a cause of grave inconvenience to the public;

(b) the number of post offices provided with public Trunk and Local Telephone facilities separaely, *vis-avis* the number of Post Offices without any telephones at the end of 1980; and

(c) by what time Government in tends to provide P. C. Os. in all the Rural Post Offices ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): (a) It is not correct to say that poor efficiency of telecommunication wing of the IVQnistry hag been a cause of grave inconvenience to the public. The Department is not able to *meet* the growing demand of telephone connections and other telecommunication facilities ag provision of adequate communication facilitiss requires considerable financial resources. These are, however, being provided in a phased manner.

The telecommunication services get affected due to power cuts impose'^ by electricity authorities, cable breakdowns caused by road digging act'vi-ties of different Civic agencie^ etc During such occasions the officers and staff of the telephone Departmont work round-the-clock in adverse conditions to set right the telephone and other services expeditiously.

(b) The information ig being collected and will be placed On the Table of the House.

(c) Public Telephones are provided in rural areas as per the liberal policy laid down by the Department. The Post Officeg covered by the policy are proposed to be proviJc-l progressively with public telephones

during the Sixth Five Year Plan (1980—85) period. This policy may not cover all the rural post offices. The policy will be reviewed at an appropriate time.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

258. **श्री कलराज मिश्र :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार के निर्माण कार्यों को हाथ में लिया गया तथा इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने पर खाद्यान्न तथा नकदी के रूप में कितना अन्न एवं धन व्यय हुआ ; और

(ख) 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसने काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया है, को अक्तूबर, 1980 में ही शुरू किया गया । इन कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों और नकद निधियों के आवंटन तथा बंटन वित्तीय वर्ष के अनुसार किए जाते हैं न कि कैलेण्डर वर्ष के अनुसार ।

इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक कुल 19.55 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है। इसके अलावा, सृजित परिसम्पत्तियों को स्थायी स्वरूप देने हेतु 57.20 करोड़ रुपये की नकद धनराशि बंटित की गई है और कार्यक्रम में काम पर लगाए गए व्यक्तियों को नकद रूप में मजदूरी का आंशिक भुगतान करने के लिए 18.30 करोड़ रुपये की अन्य धनराशि बंटित की गई है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा अब तक दी गई सूचना के अनुसार, शुरू किए गए निर्माण कार्यों के ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता के परिव्यय तथा प्रतिमान को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है अतः इसके बाद प्रस्तावित निर्माण कार्यों के ब्यौरे विकास खण्डों में तैयार किए जाएंगे । ये खण्ड स्तरीय योजनाओं का भाग होंगे और इन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

राज्यों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों तथा खाद्यान्नों की लागत पर किया गया व्यय

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र-शासित क्षेत्र	भू-संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	बृहद/लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	बाढ़ बचाव द्वारा खेती योग्य बनाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	पौधरोपण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	निर्मित/मरम्मत किए गए स्कूल भवन (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश†	—	424	—	—	2032
2	असम (असूचित)	—	—	—	—	—